



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255045
CG-DL-E-01072024-255045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]
No. 453]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

पंजाब नैशनल बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

सं.प्र.का.: पेंशन/विविध/2024(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः—

1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद यहाँ उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 के खंड (एस) में, उपखंड (डी) में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किये जाएंगे, अर्थातः -

" परंतु नवम्बर, 2012 के पहले दिवस से लागू किए गए विशेष भत्ते इसमें शामिल नहीं किये जाएंगे:-

परंतु कोई कर्मचारी जो 1 नवंबर, 2017 को बैंक की सेवाओं में था और जिसकी स्थिर वेतन वृद्धि (Stagnation increment) को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः समायोजित किया गया है, वह 1 नवंबर, 2017 से पेंशन के प्रयोजनों हेतु उक्त संशोधित स्थिर वेतन वृद्धि (Stagnation increment) के लिए आनुमानिक रूप से पात्र होगा, परंतु ऐसे पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु कोई कर्मचारी, जो बैंक की सेवा में कार्मिक के रूप में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक अथवा स्थायी आधार पर अंशकालिक वेतनमान पर नियोजित है, निष्कासित होने पर उसकी पूरी पिछली सेवा की जब्ती नहीं होगी तथा वह पेंशन संबंधी लाभों के लिए पात्र होगा। "

4. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(जी) नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न, कर्मचारी के संबंध में तीन हजार नौ सौ पिचासी रुपये प्रति माह, $\frac{1}{3}$ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, $\frac{1}{2}$ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह, और $\frac{3}{4}$ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह, जहां अंशकालिक कर्मचारी नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ हो।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में, -

(ए) उप-विनियम (1) में, —

(i) खंड (बी) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय कुटुंब पेंशन तब बंद कर दी जाएगी या अनुमत्य नहीं होगी जब पात्र पुत्र या पुत्री सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार से बारह हजार रुपये प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर देते हैं";

(ii) खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(सी) माता-पिता के मामले में, कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या अनुमत्य नहीं होगी, यदि सरकारी रोजगार या निजी क्षेत्र या स्वरोजगार से, माता-पिता में से किसी एक की आय अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय बारह हजार रुपये प्रति माह से अधिक हो जाती है।"

(बी) उप-विनियम (4) में,—

(i) खंड (ए) में, उपखंड (vi) के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(vii) नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मकारों दोनों के संबंध में केवल छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपए प्रति माह:

परंतु अप्रैल, 2021 के पहले दिवस से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि, उक्त विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी, जैसा भी मामला हो।"

(ii) खंड (बी) में, उप-खण्ड (vi) के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मकारों दोनों के संबंध में केवल छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपए प्रति माह:

परंतु अप्रैल, 2021 के पहले दिवस से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) या उक्त विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी, जैसा भी मामला हो।

(iii) खंड (सी) में, उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) नवम्बर, 2017 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए या मृत हुए कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मकारों दोनों के संबंध में केवल तेरह हजार दो सौ अस्सी:

परंतु अप्रैल, 2021 के पहले दिवस से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होंगे तथा उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में महंगाई राहत 2288 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों के लिए प्रत्येक वृद्धि पर देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परंतु मई, 2005 के पहले दिवस को अथवा उसके बाद से, उन कर्मचारियों के संबंध में, जो नवम्बर, 2002 के पहले दिवस से या उसके पश्चात किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

परंतु नवंबर, 2007 के पहले दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में महंगाई राहत 2836 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों के लिए प्रत्येक वृद्धि पर देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परंतु नवंबर, 2012 के पहले दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में महंगाई राहत 4440 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों के लिए प्रत्येक वृद्धि पर देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परंतु नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही

औसत में महंगाई राहत 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों के लिए प्रत्येक वृद्धि पर देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।”

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (एफ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“(जी) नवंबर, 2017 के पहले दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा कर्मचारियों (अधिकारियों और कर्मकारों दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक कुटुंब पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 15,880 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी तथा भत्ते का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी: परंतु मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रुपये 3985 प्रति माह होगा।
रु.15,881 से रु.31,760 तक	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और भत्ते का अतिरिक्त 20 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी: परंतु मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रुपये 4900 प्रतिमाह होगा।
रु. 31,760 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और भत्ते का अतिरिक्त 15 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी: परंतु मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रुपये 6365 प्रति माह और अधिकतम रुपये 13280 प्रति माह होगा।

(एच) अप्रैल, 2021 के पहले दिवस से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं रहेंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारियों और कर्मकारों दोनों) के संबंध में, वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगा जमा भत्ते का 30 प्रतिशत जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

उक्त विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय कर्मचारी संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों और समझौते की सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार है। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुमेश कुमार, महाप्रबंधक-मानव संसाधन विभाग

[विज्ञापन-III/4/असा./222/2024-25]

नोट:—मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या पीएनबी/आईआर/1/95, दिनांक 29 सितंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किये गये और तत्पश्चात पिछला संशोधन प्र.का.: पेंशन/विविध/2023, दिनांक 11 अगस्त, 2023 अधिसूचना द्वारा किया गया।

PUNJAB NATIONAL BANK**(Human Resources Department)****Head Office: New Delhi****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2024

No.HO: Pension/Misc/2024(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: —

“Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay, shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only, with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.”.

3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.”.

4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

“(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.”.

5. In regulation 40 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), —

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment.”;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income

of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self-employment, exceeds rupees twelve thousand per month;”;

(b) in sub-regulation (4),—

(i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4

points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

SUMESH KUMAR, (General Manager-HRD)

[ADVT.-III/4/Exty./222/2024-25]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, section 4 *vide* notification number PNB/IR/1/95, dated the 29th September, 1995 and lastly amended *vide* notification number HO: Pension/Misc/2023 dated the 11th August, 2023.